बजट के मुख्य बिंदु

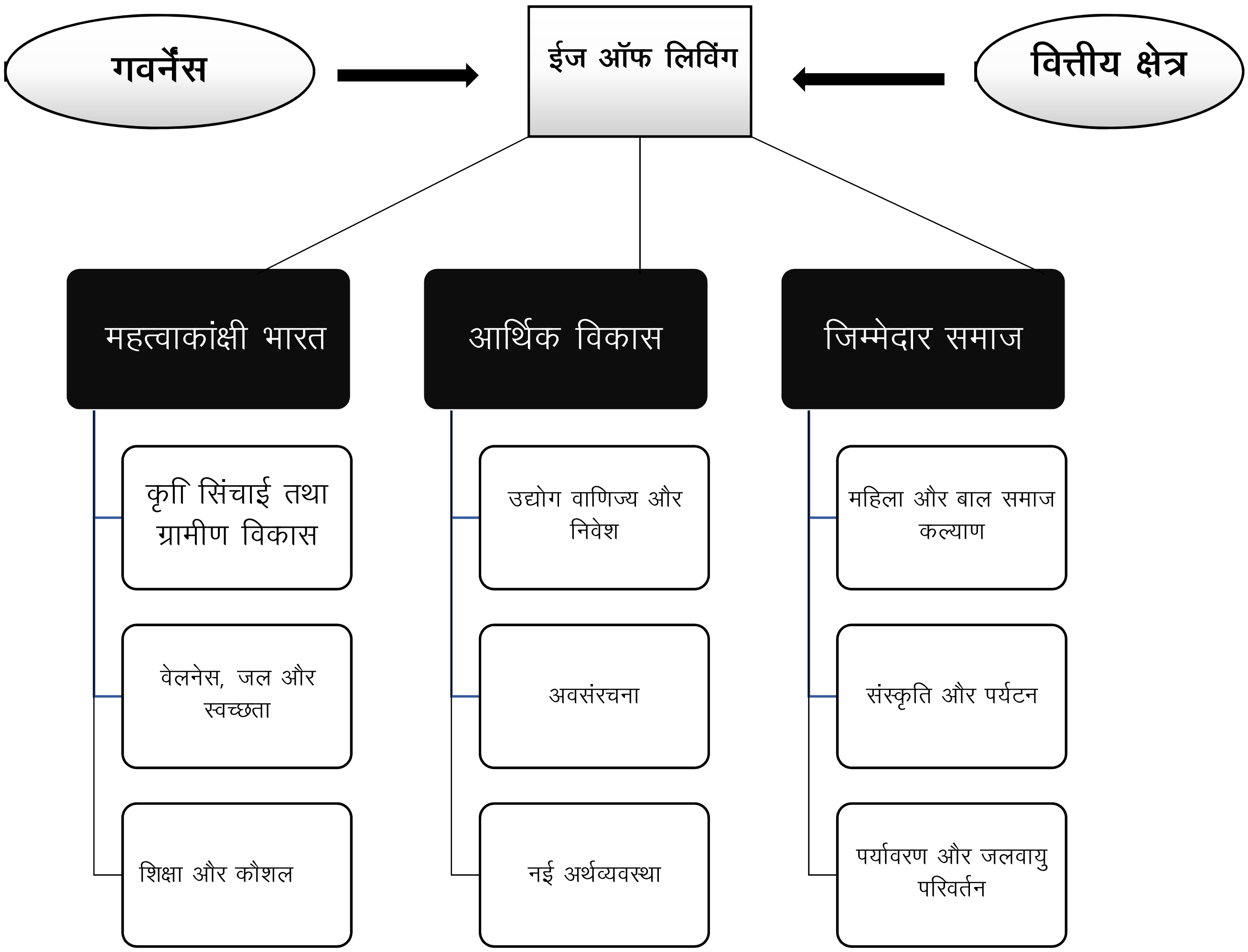

गवर्नेंस

संरचनात्मक सुधार

आईबीसी
कंपनियों के लिए आईबीसी के माध्यम से सम्मानजनक निकासी

जीएसटी
- ट्रकों के लिए टर्न अरांउड समय में 20 प्रतिशत की कटौती
- माध्यम से सम्मानजनक निकासी
- वर्धित उच्चतम सीमा और संमिश्र सीमा के माध्यम से एमएसएमई को लाभ
- औसत परिवार के लिए मासिक व्यय में लगभग 4 प्रतिशत की बचत
- पिछले दो वर्ों में 60 लाख नए करदाता शामिल किए गए और 105 करोड़ ई-वे बिल सृजित किए गए

डिजिटल क्रांति

डीबीटी अपनाना

- वर्ा 2018-19 के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए

अगला कदम

- डिजिटल गर्वनेंस
- राट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के जरिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार
- आपदा समुत्थान
- पेंशन और बीमा अभिगम्यता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा

समावेशी विकास

- निम्नलिखित पर फोकस करते हुए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" से प्रेरित गवर्नेंस:
    - निवारात्मक स्वास्थ्य देखभालः स्वच्छता और जल
    - स्वास्थ्य देखभालः आयुमान भारत
    - स्वच्छ ऊर्जाः उज्जवला और सौर ऊर्जा
    - वित्तीय समावेाण, क्रेडिट सहायता और पेंशन
    - किफायती आवासन
    - डिजिटल अभिगम्यता

वित्तीय क्षेत्र

- जमा बीमा कवरेज को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रु. करना
- सरफेसी अधिनियम के तहत ऋण वसूली हेतु एनबीएफसी के लिए पात्रता सीमा को घटाकर 100 करोड़ रुपए का आस्ति आकार या 50 लाख रु. का ऋण आकार करने का प्रस्ताव
- आईडीबीआई बैंक में सरकार की शेा धारिता को बेचने का प्रस्ताव
- सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीएआई से अलग करना

- सरकारी प्रतिभूतियों की विनिर्दिट श्रेणियों को गैर-निवासी निवेशकों के लिए खोला जाएगा
- कार्पोरेट बांड की एफपीआई सीमा को बढ़ाकर 15% करना
- नए ऋण ईटीएफ मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रस्तावित

वृहत आर्थिक संकेतक

जीडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत)

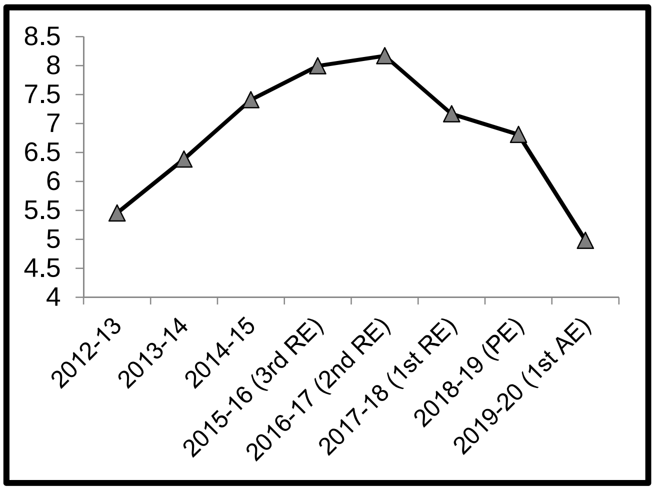

सीपीआई और डब्ल्यूपीआई (प्रतिशत)

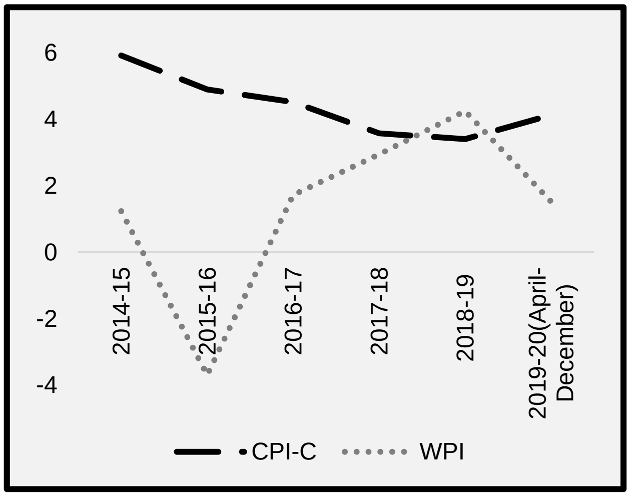

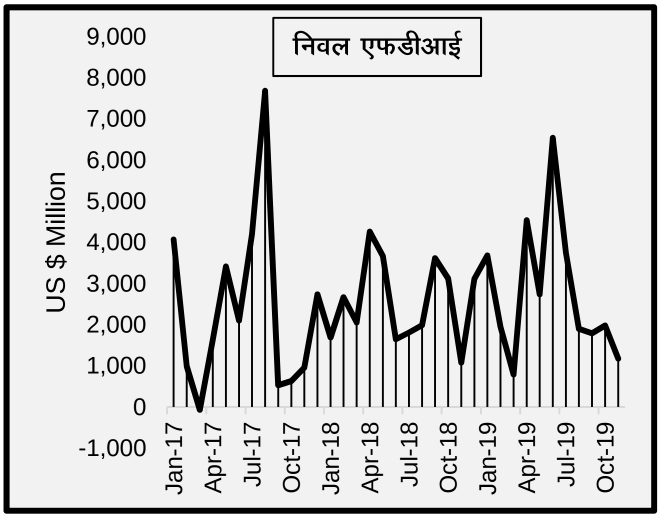

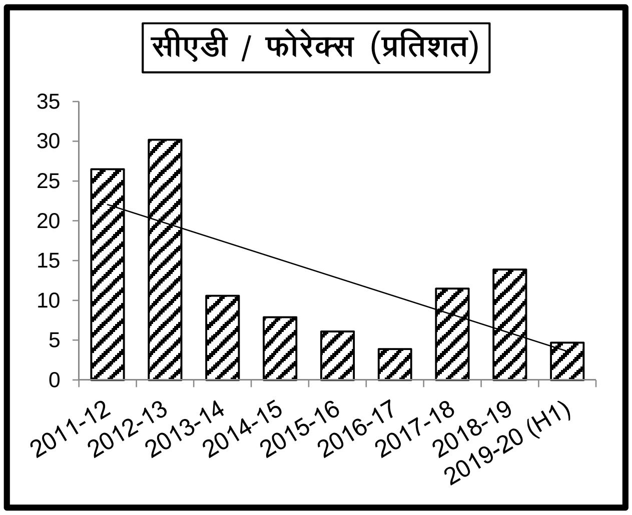

घाटों के रूझान

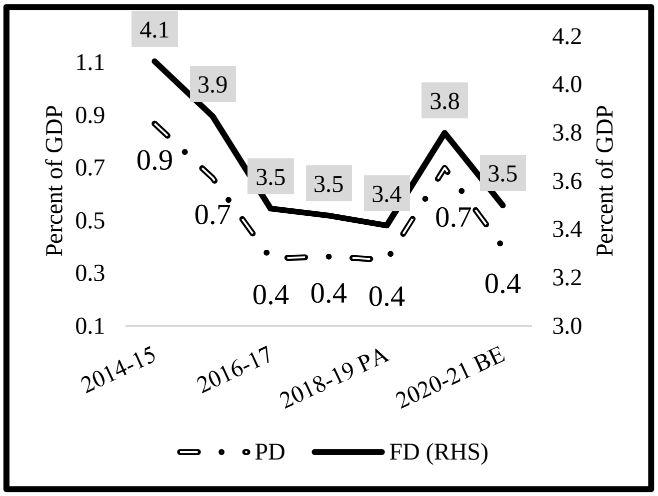

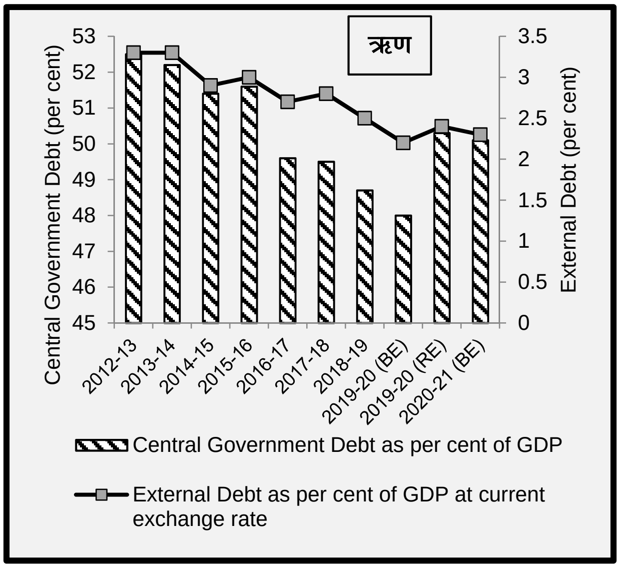

आंकड़ों के जरिए प्रगति ज्ञात करना

विदेशी विनिमय प्रारक्षित निधि (₹करोड़)

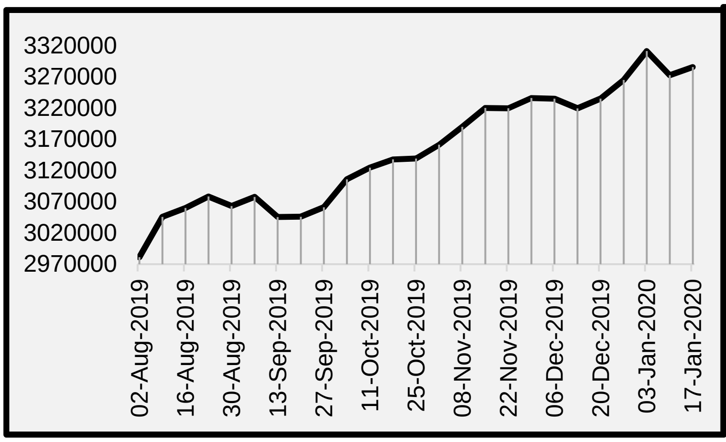

सकल बैंक ऋण (₹ करोड़)

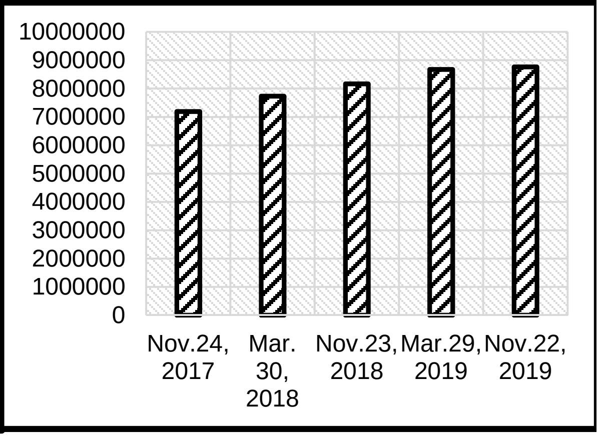

रोज़गार में स्थितियों के अनुसार कामगारों का वर्गीकरण (प्रतिशत)

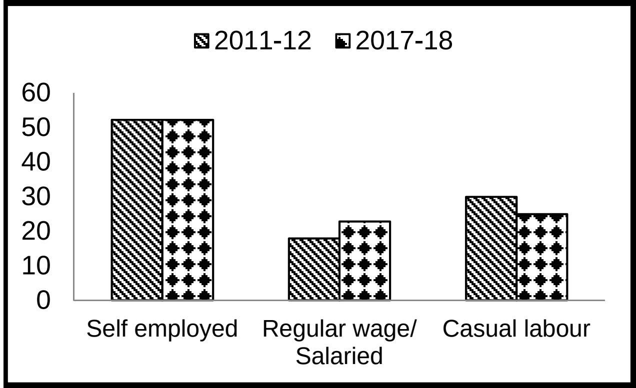

राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना

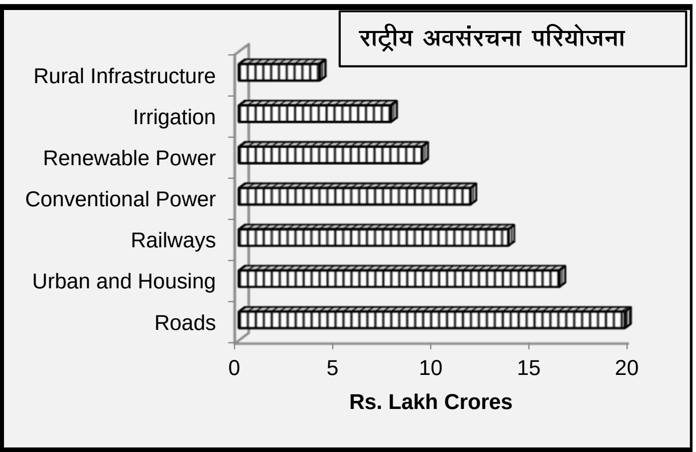

मौजूदा ट्रिलियन अमरीकी डॉलर पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भों में विश्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है

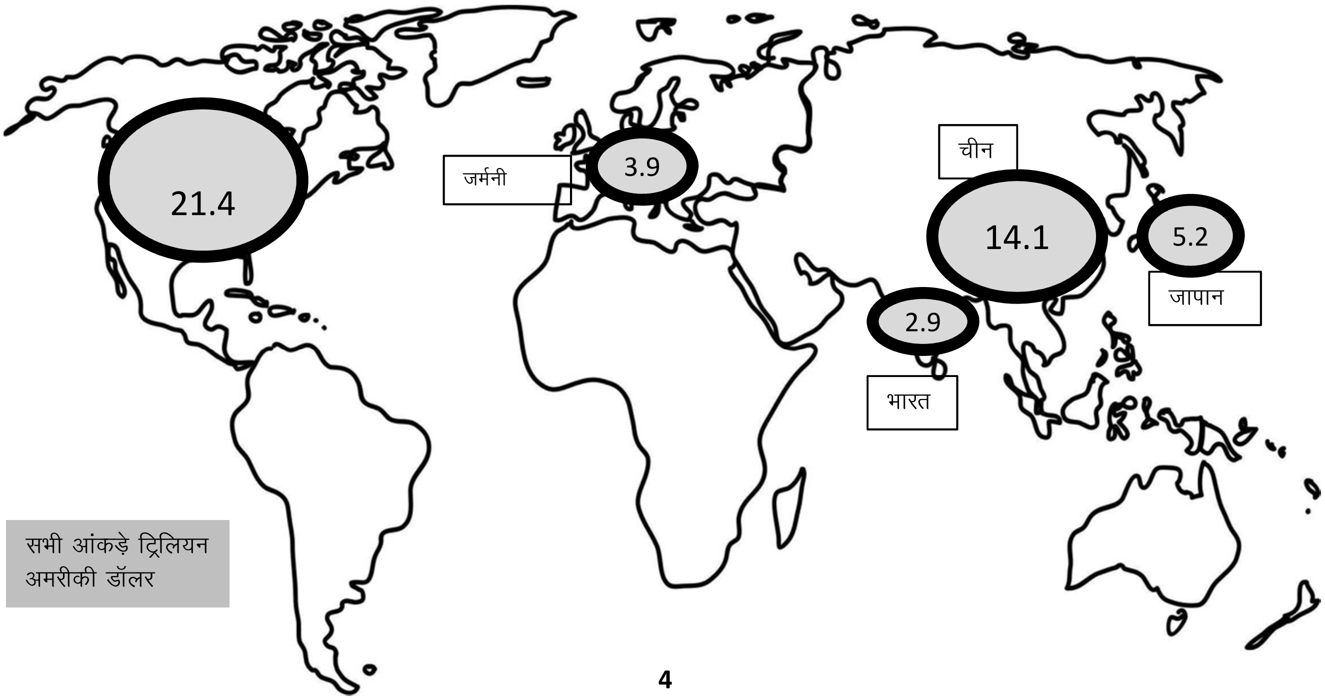

बजट का सार

राजस्व व्यय (₹ करोड़)

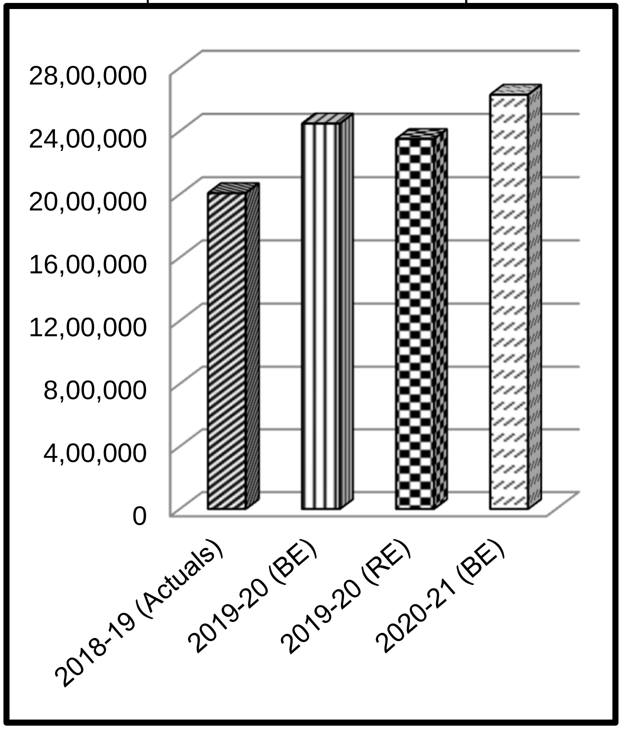

पूंजीगत व्यय (₹ करोड़)

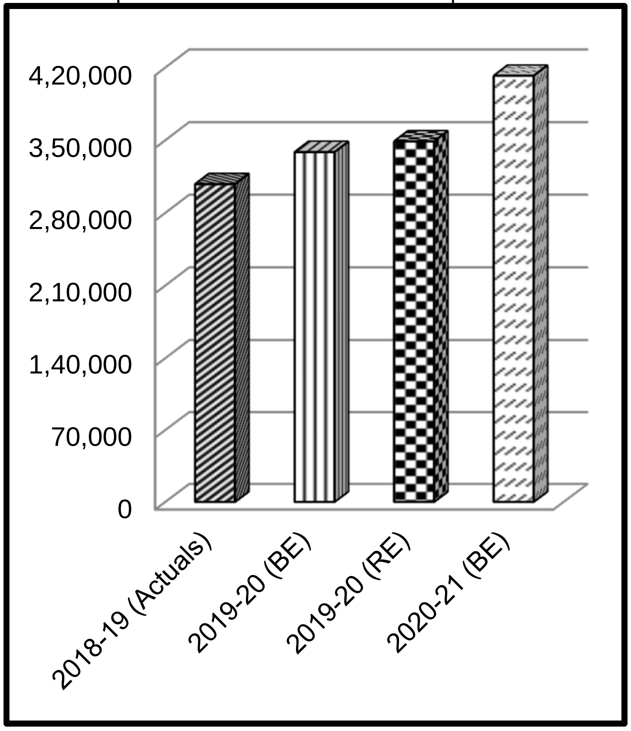

राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़)

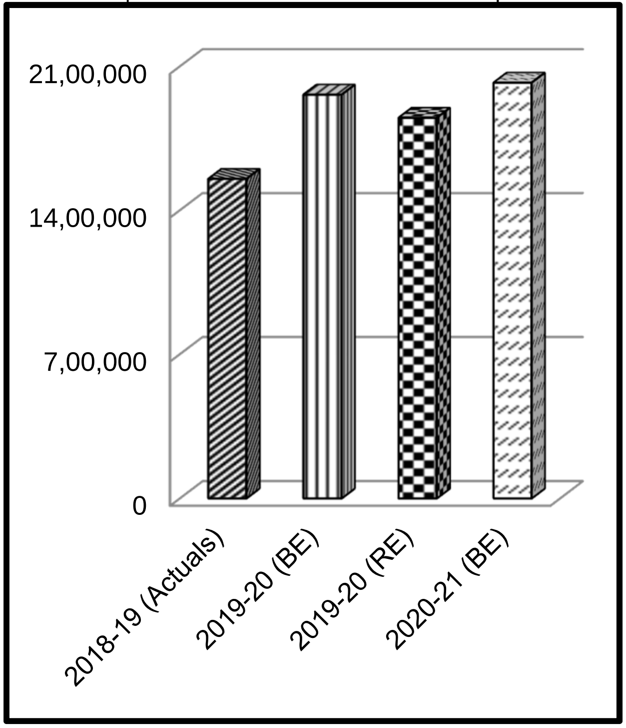

पूंजीगत प्राप्तियां (₹ करोड़)

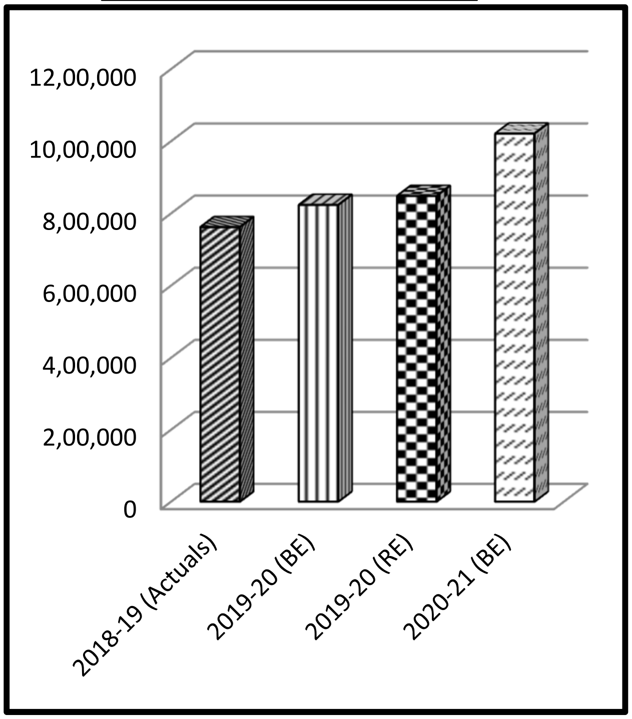

बजट का सार

रुपया आता है

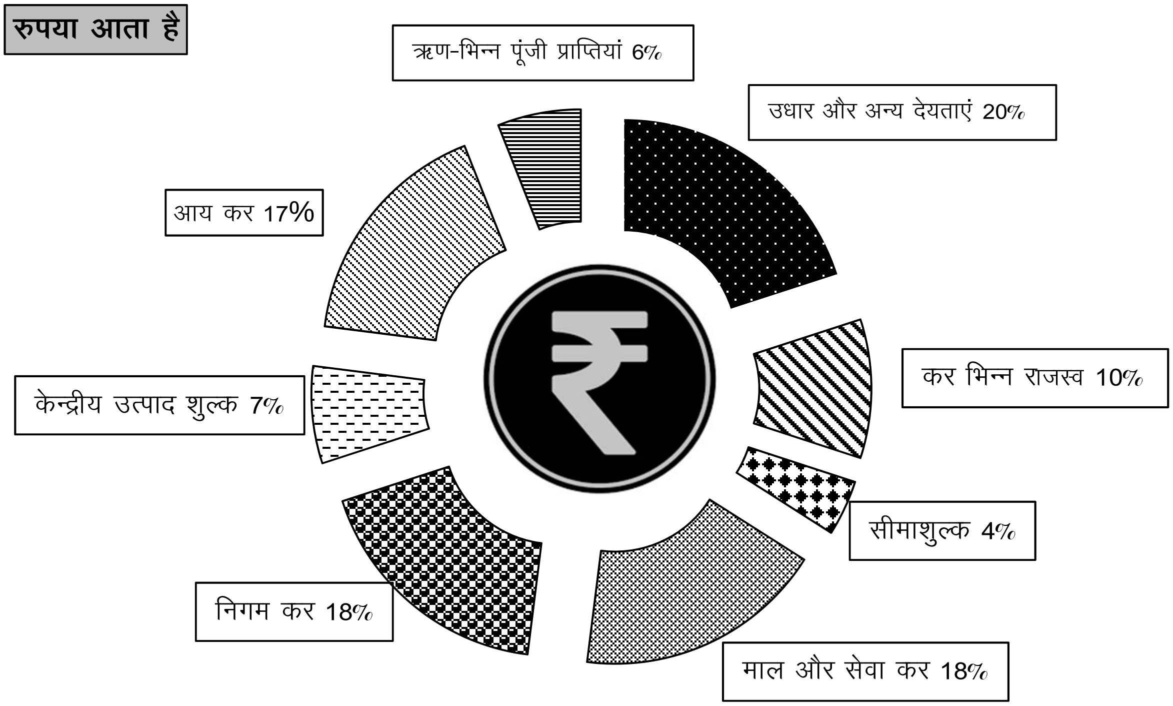

रुपया जाता है

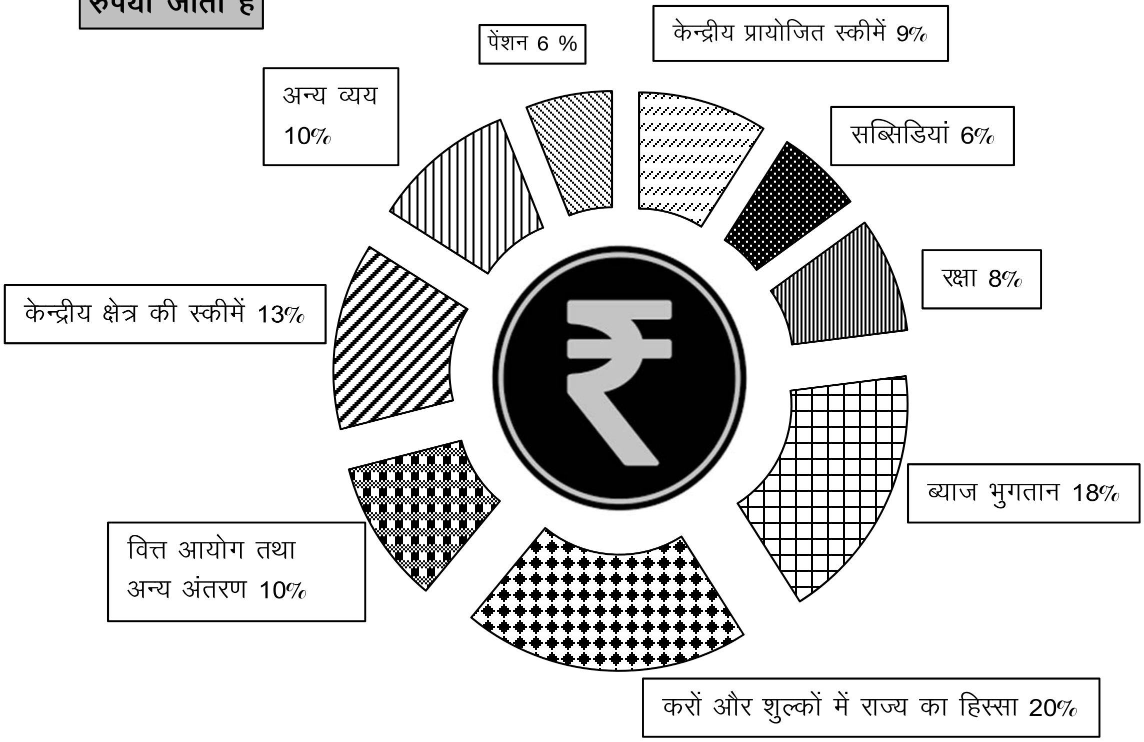

कर प्रस्ताव

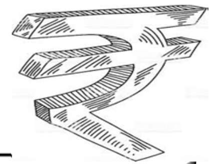

- विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र में नई घरेलू कंपनियों को 15 प्रतिशत की रियायती कारपोरेट कर दर
- विदेशी सरकारों तथा अन्य विदेशी निवेश की सॉवरेन धन निधि के लिए कर रियायत
- स्टार्ट-अप को उनके लाभों की 100 प्रतिशत कटौती करके दिए जाने वाले कर लाभों को कुल कारोबार की सीमा और पात्रता की अवधि में वृद्धि करके बढ़ाया
- सहकारी संस्थाओं के लिए रियायती कर दर का प्रस्ताव
- किफायती आवास के लिए कर लाभों से संबंधित समय-सीमा को बढ़ाना
- आसान कर अनुपालन के लिए सभी धर्मार्थ संस्थाओं को विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी करना।
- चिकित्सा उपकरणों के आयात पर स्वास्थ्य उपकर लगाना क्योंकि भारत में ये उपकरण काफी मात्रा में बनाए जाते हैं।

लाभांश संवितरण कर हटाया गया और लाभांश कराधान की क्लासिकल प्रणाली को अपनाया गया

पुरानी प्रणाली के विकल्प के रूप में सरलीकृत और नई कर प्रणाली

आय लाख में	**5 से कम**	**5-7.5**	**7.5-10**	**10-12.5**	**12.5-15**	**15 से अधिक**
कर दर (प्रतिशत)	छूट	10	15	20	25	30

अप्रैल से सरलीकृत जीएसटी विवरण को क्रियान्वित किया जाएगा। धन वापसी की प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वचालित होगी।

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास

पीएम कुसुम में स्टैण्ड अलोन सोलर पम्प हेतु 20 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा और ग्रिड से जुडे पम्पों के लिए 15 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा

- पीपीपी मोड पर कार्यक्षम वेयरहाउस के सृजन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण
- एसएचजी द्वारा चलाई जाने वाली ग्राम भंडार स्कीम का शुभारंभ
- ई-एनडब्ल्यूआर का ई-नाम के साथ एकीकरण

खराब होने वाली वस्तुओं के लिए अबाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारतीय रेलवे और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा क्रमश: ''किसान रेल'' और ''कृषि उड़ान'' की शुरूआत

- 2025 तक मवेशियों में एफएमडी तथा ब्रूसेलोसिस तथा भेंड़ और बकरियों में पीपीआर को समाप्त करना
- कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना
- 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता दुगुना करना
- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य

- 2022-23 तक 20 लाख टन का मत्स्य उत्पादन
- 45000 एकड़ जल कृषि को सहायता
- 3477 सागर मित्रों और 500 मत्स्य एफपीओ के माध्यम से मत्स्यपालन का विस्तार
- 2024-25 तक मत्स्य निर्यात बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये करना।

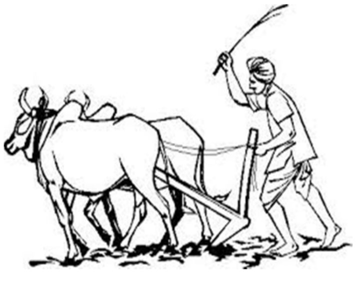

आरोग्यता, जल और स्वच्छता

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया।
- गैर-संचारी रोगों के विरूद्ध फिट इंडिया अभियान की शुरूआत

निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत कवरेज (लाख)

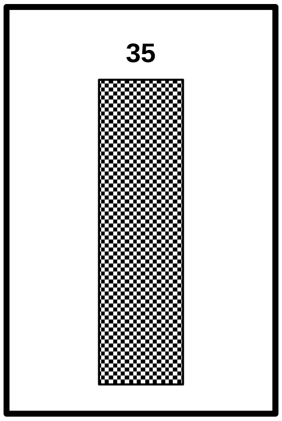

- तपेदिक को 2025 तक समाप्त करने के लिए ''टीबी हारेगा देश जीतेगा'' अभियान की शुरूआत

- पीपीपी मोड में अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यहार्यता अंतर निधियन का प्रस्ताव
- 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केन्द्र का विस्तार

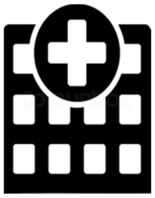

- ओडीएफ व्यवहार की वहनीयता हेतु ओडीएफ प्लस
- अपशिष्ट प्रबंधन के साथ तरल और धूसर जल प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करना

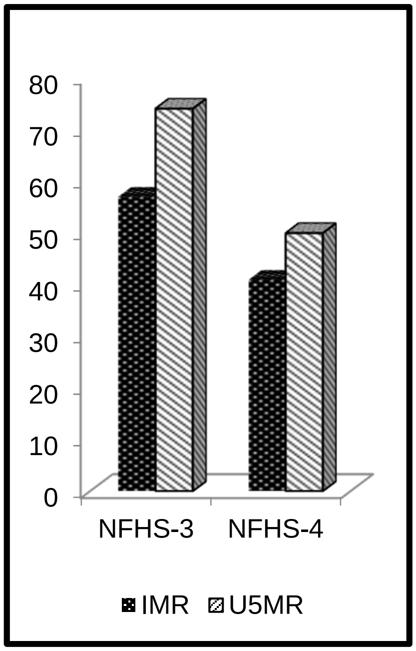

एसबीएम (करोड)

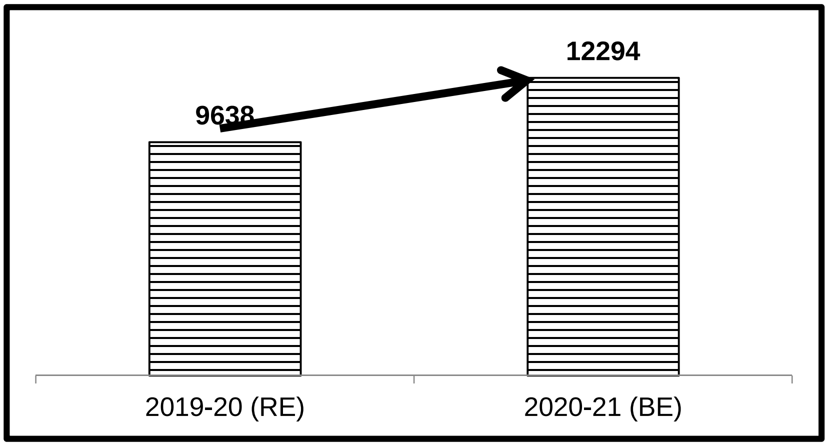

शिक्षा और कौशल

- लगभग 150 उच्चतर शिक्षा संस्थान शिक्षुता संबद्ध पाठ्यक्रमों की शुरूआत करेंगे
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नए इंजीनियरों को प्रशिक्षु अवसर
- विदेश में रोजगार चाहने वालों की दक्षता में सुधार लाने हेतु विशेष ब्रिज पाठ्यक्रम

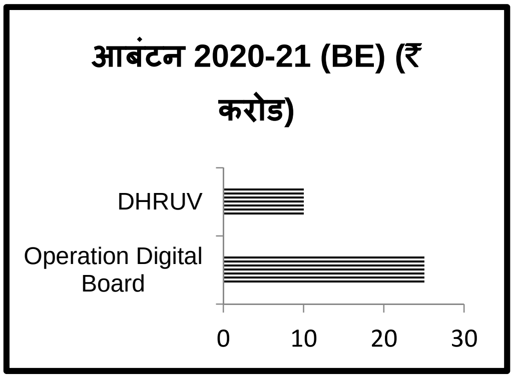

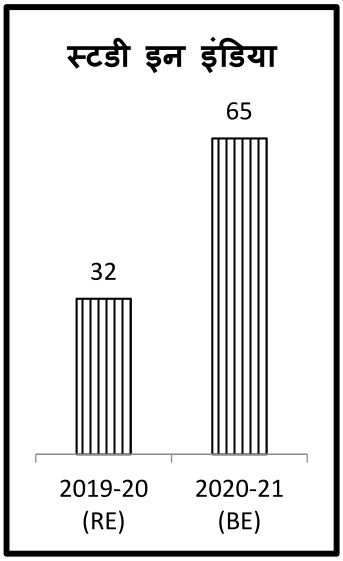

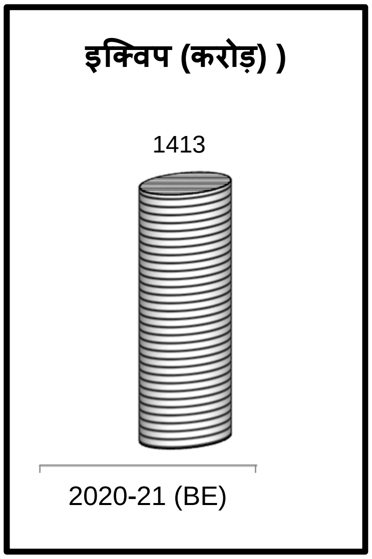

- समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इन्ड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन

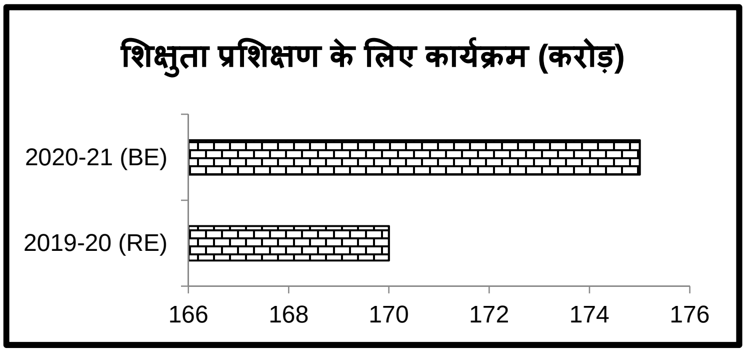

नई अर्थव्यवस्था

- प्रौद्योगिकी के उभरते सेक्टरों के लिए ज्ञान अनुवाद क्लस्टर।
- टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स हार्बरिंग टेस्ट बेड्स और छोटे स्तर की विनिर्माणकारी सुविधाओं को बढ़ाना।
- 8000 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय प्रमात्रा प्रौद्योगिकियां और अनुप्रयोग मिशन का प्रस्ताव

उद्योग, वाणिज्य और निवेश

- मोबाइल फोन, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण के प्रोत्साहन हेतु योजना
- 4 वर्ष तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन

- अधिक निर्यात ऋण वितरण के लिए निर्विक योजना प्रारंभ की गई
- अंतिम छोर तक सुविधा प्रदान करने के लिए निवेश क्लियरेंस प्रकोष्ठ की स्थापना

- ट्रेड्स के माध्यम से एमएसएमई को बीजक वित्तपोषण का विस्तार
- एमएसएमई के उद्यमियों को अधीनस्थ ऋण प्रदान करने की योजना।
- निर्यात बाजारों में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए एक्जिम बैंक और सिडबी द्वारा योजना का शुभारम्भ

कार्पोरेट कर दर कटौती

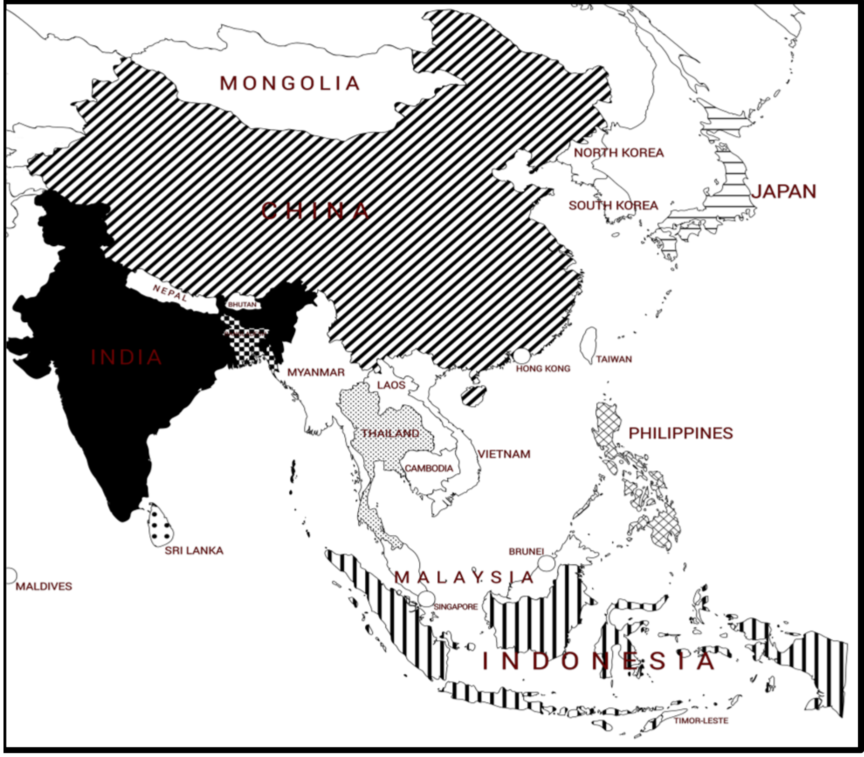

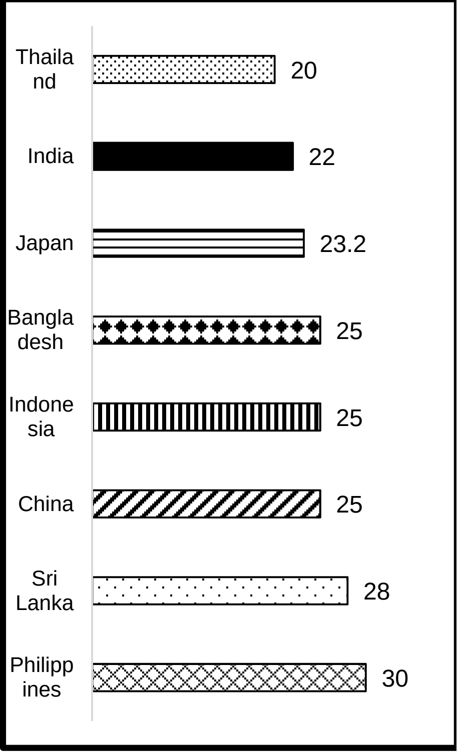

अवसंरचना

- राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति शीघ्र ही शुरू की जाएगी।
- सड़कें: राजमार्गों का तेजी से विकास।
- लर्निंग लाइसेंस वाहन पंजीकरण का ऑनलाइन निर्गमन।
- रेल: चार स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं
- पीपीपी विधि के जरिए 150 यात्री रेल गाड़ियां
- पर्यटन स्थलों के लिए तेजस जैसी और अधिक रेलगाड़ियां
- पत्तन: कम से कम एक बड़े पत्तन का निगमीकरण
- हवाई अड्डे : 100 और हवाई अड्डों को उड़ान योजना के अंतर्गत पुन: विकसित किया जाएगा।

विद्युत: परम्परागत ऊर्जा मीटरों के स्थान पवर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना।

गैस ग्रिड: राष्ट्रीय गैस ग्रिड का 27,000 किमी0 तक विस्तार

- अवसंरचना वित्तपोषण: 103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं की घोषणा की गई
- गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी

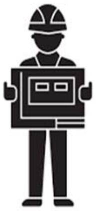

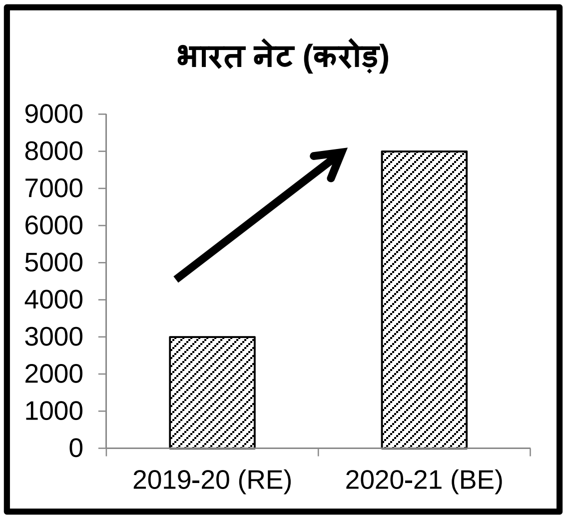

तेजी से सड़क विकास

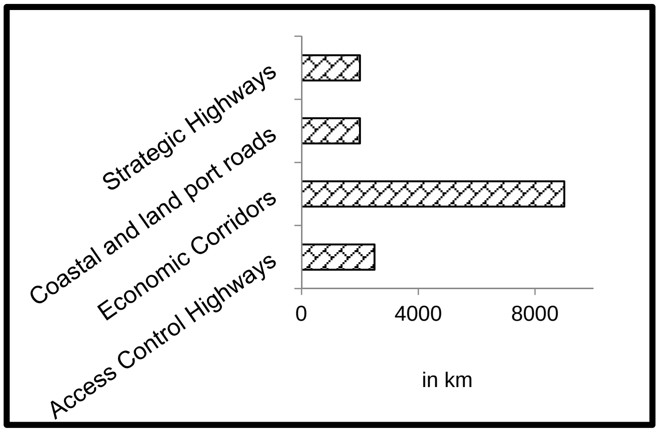

ध्यान रखने वाला समाज

महिला और बाल; समाज कल्याण

- 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए गए।
- मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और पोषण स्तर सुधारने के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक कार्य बल गठित किया जाएगा।

संस्कृति संस्कृति और पर्यटन

- भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव।
- 5 पुरातात्विक स्थल दर्शनीय (आईकानिक) स्थलों के रूप में विकसित किए जाएंगे।
- मुद्रा विषयक एवं व्यापार संबंधी एक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
- रांची में जनजातीय संग्रहालय।
- लोथल में समुद्री संग्रहालय की स्थापना

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- आपदा समुत्थान अवसंरचना सम्मेलन का सितम्बर, 2019 में शुभारंभ
- 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों में अधिक स्वच्छ हवा के लिए योजनाएं लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन

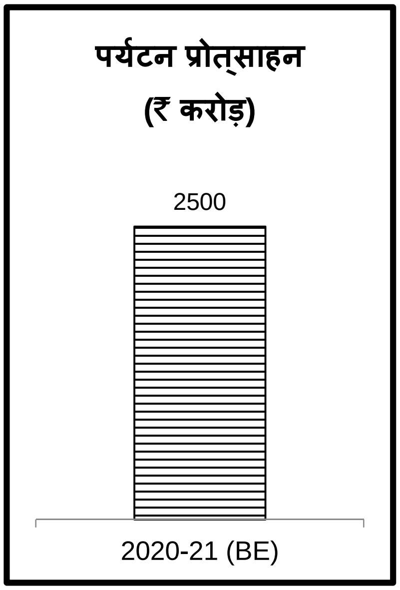

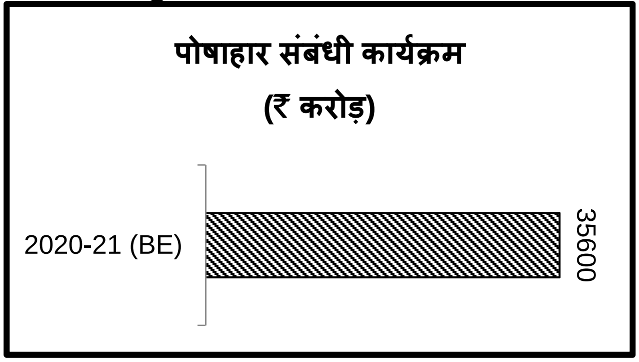

प्रमुख स्कीमों को बजट आबंटन

In ₹ crore

पीएम किसान योजना

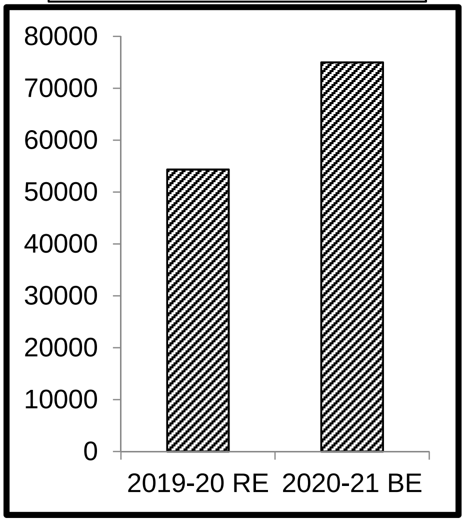

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

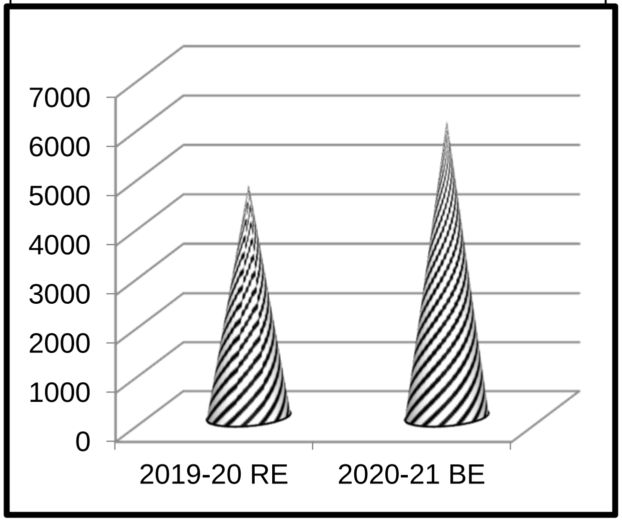

डीबीटी एलपीजी

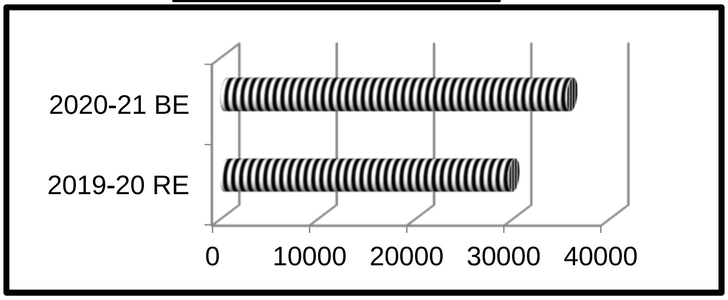

आईसीडीएस

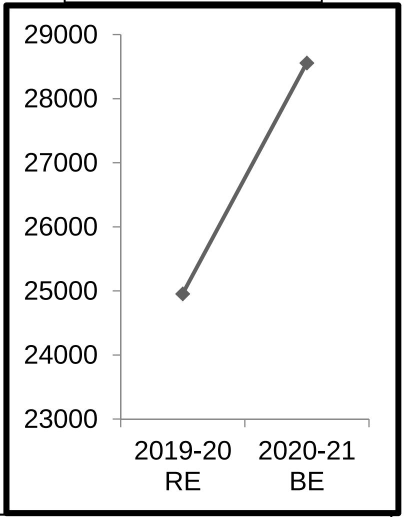

प्रधानमंत्री आवास योजना

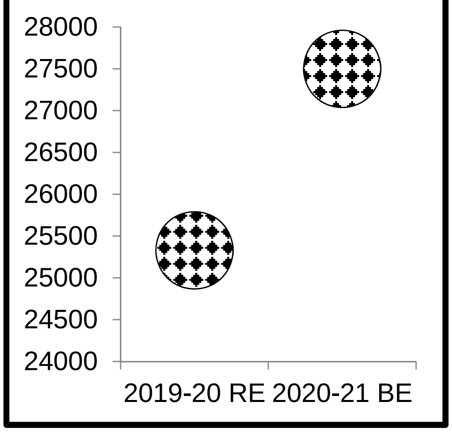

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

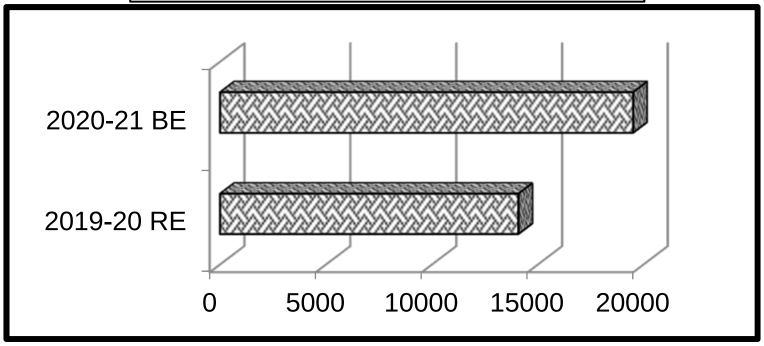

प्रमुख मंत्रालयों का बजट प्रावधान 2020-21

₹ करोड़

₹ 50040	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
₹ 67112	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
₹ 72216	रेल मंत्रालय
₹ 91823	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
₹ 99312	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
₹ 122398	ग्रामीण विकास मंत्रालय
₹ 124535	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
₹ 142762	कृि और किसान कल्याण मंत्रालय
₹ 167250	गृह मंत्रालय
₹ 471378	रक्षा मंत्रालय